[श्री ईश दत्त यादव]

बड़ी रेल लाइन नहीं हैं। शाहगंज से बनारस तक तो बड़ी रेल लाइन है, लेकिन शाहगंज से बलिया के बीच में बड़ी लाइन न होने के कारण इन तीन चार जिलों में कोई उद्योग नहीं लग सके। मान्यवर, मैंने पिछले सत्र में इसी विषय को उठाया था और भूतपूर्व रेल मंत्री जार्ज फ़र्नांडीस साहब से अनुरोध किया था जब वह 29 अक्तूबर, 90 को मऊ में बड़ी लाइन पर रेल गाड़ी चलाने के लिए गये थे। उन्होंने घोषणा भी की थी कि बलिया से शाहगंज तक बड़ी रेल लाइन बना दी जायेगी, उस पर काम शुरू कर दिया जायेगा। लेकिन मेरी यह जानकारी है कि इस संबंध में रेल विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। यह अत्यंत आवश्यक है इसीलिए मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यद्यपि सौभाग्य से हमारे प्रधान मंत्री और माननीय रेल मंत्री दोनों उसी जनपद बलिया के रहने वाले हैं। मैं उन लोगों के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वे इस ओर ध्यान देकर अगले बजट में छोटी रेल लाइन को बलिया से शाहगंज तक बड़ी लाइन में कन्वर्ट करने की घोषणा करके तत्काल कार्रवाई शुरू करायें।

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : मैं आपकी अनुमति से जो प्रश्न ईश दत्त यादव ने रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं। इसी से अपने को सम्बद्ध करते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी सदन में 6 बार इसी सवाल को मैंने उठाया था और सरकार की तरफ़ से मंत्री महोदय ने आश्वासन भी दिया था।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : आपका नाम भी इस से सम्बद्ध मान लिया गया है।

श्री राम नरेश यादव : मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान देकर काम को पूरा करे जिससे शाहगंज से बलिया तक छोटी लाइन बड़ी लाइन में परिवर्तित हो सके।

श्री चतुरानन मिश्र : जब तक लाइन बने तब तक कोई कारखाना तो वहां खोल दें। जब तक माल तैयार होगा तब तक रेल लाइन तैयार हो जायेगी।

श्री ईश दत्त यादव : जब तक बड़ी लाइन नहीं बनेगी तब तक कारखाना कैसे लग सकेगा।

STATUTORY RESOLUTION SEEKKING APPROVAL OF PRESIDENT'S PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO GOA—Contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Now, we are taking up the Statutory Resolu-" tion regarding President's rule in the State of Goa Yesterday, Shri Bagrodia. was speaking and he will continue. •

श्री संतोष बागड़ोदिया (राजस्थान) महोदय, आपको मैं बहुत धन्य वाद देता हूं। कल जब मैं बोलने खड़ा हुआ तो एकदम बीच में ब्रेक लगा दी। जिस परिस्थिति में आज गोवा हो गया, जैसी परिस्थिति गोवा की बनी है मेरी समझ में वहां के गवर्नर के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं था। गवर्नर ने पूरी छूट दी असेम्बली के मेम्बरों को। जो भी लीडर थे उनको बुलाकर कहा कि आप अगर अपनी मेज्योरिटी प्रूव कर सकते हों तो असेम्बली में करो। उन्होंने दिसम्बर की दस तारीख तय भी की। लेकिन उस समय जो एम जी पी के गोवा के मुख्य मंत्री थे उन्होंने दस तारीख की सुबह ही रिजाइन कर दिया। गवर्नर साहब के पास कोई और चारा नहीं रह गया था। उन्होंने देखा कि कोई भी ऐसा लीडर वहां नहीं है जो सरकार को मजबूती से चला सके। उनको आखिर में यही रिकमेंड करना पड़ा। सेन्टर के पास इस व्यवस्था के अलावा कोई और उपाय नहीं था। उन्होंने प्रेजीडेंट रूल लागू कर दिया। अभी भी असेम्बली एनिमेटेड सस्पेंशन में है, पूरी तरह भंग नहीं हुई है। मेरा अनुरोध है गृह मंत्री महोदय से कि असेम्बली को इस तरह

से चालू रखने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। अगर इसमें देर होती रही तो वहां होर्स ट्रेडिंग चालू हो जायेगी। उसको डिजोल्व कर दीजिए और जल्दी से जल्दी वहां इलेक्शन करा दीजिए। अगर इस तरह से इसको रोकेंगे तो होर्स ट्रेडिंग शुरू हो जायेगी। (व्यवधान)

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Will you yield for a minute?

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Yes.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR; The Resolution which I have with me states "That this House approves the Proclamation issued by the President on the 14th December, 1990 under article 36 of the Constitution, in relation io the State of Goa. " This is the Resolution that is circulated to me today. Under article 36...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Mr. Pra-kash Ambedkar, please hear me. You have already given your name. You are the next speaker.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: I am on a different point. ... *(Interrupt'ons)*... It is a point of order.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Now the Office says that it is a printing mistake. Please take your seat.

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR; I hope that it will be corrected.

SHRI CHATURANAN JMISHRA (Bihar): If it is a printing mistake, then what is the correct thing? Before you say mis is corrected, we will not take it to be corrected. Only you have the right to say that and nobody else. What is the correct thing? Only after knowing that, the House can proceed. Otherwise, Mr. Prakash Yashwant will be correct.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Mr. Prakash Yashwant and Mr. Chaturanan Mishra, for your information, I want to tell you that you know that I ajway speak in Hindi from there. Here is tha Hindi version of the paper. I am reading Here it is right.

जो हिन्दी वर्शन है वह करेक्ट है। अंग्रेजी वर्शन में गलती हुई, वह करेक्ट कर दी गई है। अब आप बैठ जाइये, उनको अपनी बात पूरी करने दीजिये।

श्री चतुरानन मिश्र : इसको पढ़ दीजिये और आगे से कह दीजिये कि हिन्दी वर्शन बराबर करेक्ट रहेगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : हिन्दी वर्शन इस समय करेक्ट है। इसमें लिखा हैं, यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन गोवा राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 14 दिसम्बर 1990 को जारी की गई उदघोषणा का अनुमोदन करती है।

श्री संतोष बागड़ोदिया : महोदय, कल मेरे से पहले डी.एम.के. के सदस्य श्री गोपालसामी बोल रहे थे कि यह जो डिफ़ेक्शन हुआ, यह कांग्रेस ने करवाया है और उसके कारण देश में गड़बड़ी होती है और इसी कारण से राज्यों में इधर-उधर और उलट-पलट होती हैं, चीफ़ मिनिस्टरों को हटाया जाता है। मैं कहता हूं कि डी.एम.के. वाले पिछले एक साल तक एन.एफ़. गवर्नमेंट के पार्टनर थे और वह जानते हैं कि कहां-कहां कई सरकारों को इन्होंने तोड़ा है, जैसे नागालैंड और मिजोरम में इन्होंने तोड़फ़ोड़ की, डिफ़ेक्शन करवाया। गोवा में भी इन्होंने ही डिफ़ेक्शन करवाया। आज ये बोल रहे हैं कि वहां पर गवर्नर रूल क्यों करवाया हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये आपोज करने के लिए ही अपोजीशन करते हैं? ये नियम कायदों को नहीं समझना चाहते हैं। सिद्धान्तों से इनको कोई मतलब नहीं है। इनका मतलब होता है कि किसी तरह से कुर्सी बनी रहे।

श्रीमती सुषमा स्वराज (हरियाणा) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, अभी माननीय

[श्रीमती सुषमा स्वराज]

सदस्य ने एक तथ्य गलत कहा कि नागालैंड और मिजोरम की सरकारें गिरी। मिजोरम में कभी सरकार नहीं टूटी, कभी नहीं गिरी। वहां कांग्रेस-आई की सरकार भी वही चल रही है। रिकार्ड स्ट्रेट रखने के लिए मैं कह रही हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : माननीय सदस्य से मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि मिजोरम के बारे में कुछ ऐसी बात न बोलें जिससे माननीय सदस्या को तकलीफ़ हो।

SHRI SANTOSH BAGRODIA: Madam, I stand corrected.

श्रीमती सुषमा स्वराज : इसमें तकलीफ़ की बात नहीं है, यह तथ्य की बात है।

श्री संतोष बागड़ोदिया : माननीय सदस्या के दर्द को मैं समझता हूं और उसके लिए माफ़ी मांगता हूं। माननीय सदस्या हमारी बहिन हैं, उनसे हम हजार दफ़े माफ़ी मांग सकते हैं।

मैं यह कहना चाहता हूं कि जब यह खिचड़ी सरकार बनी तो तीन-चार महीने भी नहीं चल सकी। लेकिन फ़िर भी ये लोग कांग्रेस को दोष देते हैं। आप जानते हैं कि एन्टी-डिफ़ेक्शन बिल लाने की हिम्मत श्री राजीव गांधी जी ने की थी। डिफ़ेक्शन का चक्कर तो ये लोग लाते हैं। कांग्रेस से कभी डिफ़ेक्शन नहीं हुआ। कांग्रेस से जो लोग गये वे भी कांग्रेस में अपने आप वापस आ गये और आज भी आना चाहते हैं...(**व्यवधान**)। माथुर साहब इधर आ रहे हैं।

श्री चतुरानन मिश्र : श्रीमन्, मेरा पाइन्ट आफ़ आर्डर है। माननीय सदस्य ओस कर रहे हैं।

श्री संतोष बागड़ोदिया : अंत में मैं कहना चाहता हूं कि यह जो स्टेट्यूटरी रिजोल्यूशन होम मिनिस्टर ने दिया है कि गोवा में प्रेज़िडेन्ट रूल लागू किया जाय उसका मैं समर्थन करता हूं।

3.00 P. M....

SHRI PRAKASH YASHWANT AMBEDKAR: Mr. Vice-Chairman, Sir, the proclamation of President's Rule in Goa has to be viewed in a different context. I am saying it in a different context because in Goa, we had the position in which the Ministry failed to function. I will not go into the question as to who has brought about a defection or as to how many persons have crossed ' over. But there is no condition in Goa where the elections cannot be held. I fail to understand the stand taken by the Government in postponing the elections or ordering fresh elections to take place. These are emergency powers and these emergency powers, if we keep on misusing them and wait for a position in which either one party, which is the ruling party or the supporting party comes into prominence or comes into such a position where they can form a Government later on, I think, we will be pushing the people into a state where they will revolt against the Central Government. I would like to make one thing absolutely clear that the younger generation which is there in this country is without any aims and objects. When I say that they are without any aims and objects, that means they do not have any goal before them, they can be easily manipulated and in what way they can be manipulated in this country, we have seen. Where there is President's rule, we have seen the amount of corruption, we have seen the administrative failure and we have also seen that there is a gap between the Government and the masses which is developing today. What is essential today is to see that we bridge: this gap. We do not bring one more State on the map of India which can be called a State which represents unrest and therefore, I oppose this motion and request the Government to see that there is no condition in which we cannot hold the elections. The elections can be held at any time. It is legitimate that in every democracy where a Government fails, we should not fail to face the elections. We have accepted democracy as a part of our life. If we have accepted democracy as a part of our life, we will have to pay for that. If we are going to say that it is going to cost the nation. I

does not cost the nation and therefore, in the interest of democracy, in the interest of younger generation, I will say, let them have their own Government, let them have a Government which represents them, let them have a Government which they can fight against. Let us not create a position in which the Centre takes the blame. We have been doing it in many States and therefore every accusing finger that is being pointed out, it is being pointed out at the Centre, I will say and not at the State, which should have been the case. Therefore, it is my honest request to the present Government to see that while they are bringing in this resolution, they give a time-limit in which they can say that they are holding the elections. With these words, I thank you.

SHRIMATI MARGARET ALVA (Karnataka): Hon. Vice-Chairman, if I may point out, the present Political state in Goa comes basically out of the effort that was made by the National Front Government to destablise a Government which had been functioning normally. It is a known fact. It was stated in the House. Here, I know someone or the other is trying to interrupt or contradict me, but it is on record of the House. When this happened in Goa, in this House itself an issue was raised that a Union Minister went there, literally sat in Goa when the Chief Minister was out of town, and manipulated the defections in such a way, Mr. Vice-Chairman, that they went to the extent of making the Speaker of the Assembly a defector. The Speaker who was supposed to be responsible for enforcing the Anti-Defection Law, himself changed his party and became a defector and then sat in judgement to see whether or not a State Government could function and whether or not one was on this side or that side and whose split or change was acceptable or not. It was a question of the culprit becoming the judge and that is where the original problem started and, Sir, as if this was not bad enough, they went ahead and had the Governor swear in the very defector-Speaker as the Chief Minister of Goa at a later stage, literally giving respectability to a defector who had from his chair jumped into the Chief Minister's chair through the act of defection. Sir, this is where the problem started. If anything, at that time this man could have been told where his place . was and a decision in keeping with the Anti-Defection Law could have been taken so that the present situation would not have arisen. What Happens today is that the Speaker-turned-defector-turned Chief Minister is disqualified from the membership of the House, again because of the Anti-Defection Law. In this confusion, of course, there was a state of instability at a particular stage, and perhaps the Governor was justified in saying that until the situation became clear, normal administration had become difficult; it is very difficult to say who belongs where and, therefore, the Assembly was suspended temporarily and Governor's rule was imposed...

SHRI SANGH PRIYA GAUTAM: Madam, the Governor recommended dissolution.

उपसभा पक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): मैं बीच में व्यवधान मत डालिये।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा: बीच में मत बोलिये। आप भी बोलियेगा। मैं कभी किसी को डिस्टर्ब नहीं करती।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Please mention your own points.

SHRIMATI MARGARET ALVA: Let me point out, Sir, that there is today a situation in Goa where you have President's rule. I hold nothing against any officer or anybody but I would like to point out to the Government that they have broken a long-standing tradition of this country. We have had President's rule in other States, Karnataka, Assam, everywhere. The convention has always been that you don't send an officer who belongs to the State as an Adviser during President's rule. After all, you have your own Chief Secretary, you have your own cadre, but you don't send during Governor's rule anybody to the State who belongs to that State. In Goa you sent

[Sbximati Margaret Alva]

an officer who belongs to the State, maybe, to another cadre, but who belongs to the State, to run the administration. And Sir, to make matters worse—I must point out to the hon. Home Minister—you have in the middle of this crisis transferred the Governor to Karnataka. Where was the hurry to shift the Governor during President's rule? There is no Chief Minister. There is no Government. You send an officer and you shift the Governor. You want this officer to be the Governor, to be the Chief Minister, to be the Administrator... ?

SHRI PARVATHANENI UPENDRA (Andhra Pradesh): Additional charge.

SHRIMATI MARGARET ALVA: You sit in Bangalore and run Goa? What is the idea of having a situation like this? Is there such a shortage of Governors in this country? I know there has been a lot of confusion created by the previous Government with coming and going...

SHRI PARVATHANENI UPENDRA: Your Government.

SHRIMATI MARGARET ALVA: No, the previous Government. It was created by the National Front Government. Sir, I am just pointing out that Goa does not de]serve this kind of treatment. There should be a litiie bit of introspection on why there was need for creating this confusion after you bad imposed President's rule. I am told that the Adviser is sitting in the Chief Minister's chair, in the , Chief Minister's chambc, and has occupied the Chief Minister's house. This has never happened in any State during President's rule ever before. I would request that these issues may please be looted into. Someone said there should be elections. I don't think there should be elections immediately because the MLAs have been elected for a five-year period with a mandate of the people. Three or four o- five of them have violated the mandate of the people. And why should you make all the MLAs in the State Assembly pay the price of defection because the credibility of four or five of them has been lost? Let them be disqualified. Let theai lost their seats, if necessary. Let that be looked into. I think that the time has come when an opportunity should be given for the normal democratic process to take its shape. The Assembly should be revitalised, should he called and the person who claims that he can form a Government with a certain credible majority should be given an opportunity to prove his strength on the floor of the House. Only then will the real democratic process in Goa iake root. Goa has had a certain tradition; it has its own identity. Although there have been various kinds of pulls and pressures, Goa has really not fallen into the normal norms in other States. In Goa ihey have their own cultural identity. But I would request the honourable Minister, dissolution of the Assembly is not the answer. It is too expensive an affair at this time. If *it* cannot be done in many other States, why only in Goa should you ask the MLAs to go back to the electorate for a fresh mandate? I would request the honourable Minister to explorj the possibility of having the Assembly restored. Please give a full-time Governor to Goa who can run the administration immediately and take decisions. And please ensure that when there are 38 elected MLAs in Goa, they are not left or thrown to the mercy of some Adviser or some officer who goes there like an overload. Please let a democratic Government function in Goa. Please ensure that the process of President's rule is not kept going for so long that horse-tradina, money and all other factors come to play just to buy up, just to change, these various groups. With these words I certainly would support the President's rule for a very short spell but hope that the popular Government will be restored soon.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAI. SINGH(. Now Shrimati Kamla Sinha. She is the last speaker. Then the Minister will give his reply.

श्रीमती कमला सिन्हा (बिहार): महोदय, काफी बातें हो चुकी हैं । मुझे कुछ विशेष कहना नहीं है। मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि संघीय गणराज्य में लोकतंत्र पद्धत्ति से जहां सरकार चलती है वहां किसी भी प्रांत में किसी भी कारण से

असेम्बली को एक लम्बे समय तक एनीमेटेड सस्पेंशन में रखना, असेम्बली को डिसाल्व करना, यह अच्छी बातें नहीं है और जितनी जल्दी हो सके गोवा में सरकार की पुर्नस्थापना हो जाए, वहां पापूलर गवर्नमेंट को रेस्टोर किया जाए तथा असेम्बली को फंक्शनल कर दिया जाए । अगर आज की परिस्थिति में यह संभव नहीं है तो असेम्बली को डिसाल्व करा कर जल्दी वहां चुनाव करा दिये जाएं ।

गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कान्त सहाय) : सभापति महोदय, तमाम माननीय सदस्यों के द्वारा एक खास बात उभर कर आई है कि जहां चुनी हुई सरकारें बन सकती हैं वहां अविलम्ब बनाने की प्रक्रिया की जाए । मैंने आपको बताया था कि वहां कुछ दुर्भाग्यपूर्ण राजनैतिक स्थिति रही जिससे कि स्थायी सरकारें नहीं बन पायीं और एक साल से कम की अवधि में वहां सरकारें बदलीं । अभी जो पूरे देश के हालात हैं, जो स्थिति है उसमें हम अगर वहां प्रेजीडेंट रूल लगाकर, असेम्बली डिसाल्व करके अपनी बात किये होते तो माननीय सदस्यों की यह भी राय उभर कर आती कि वहां चुनी हुई सरकार बनाने की प्रक्रिया क्यों नहीं की गयी । इसलिए इन तमाम पहलुओं को देखते हुए वहां के गवर्नर को जो अपनी राय थी उस राय के बावजूद भी एक आखिरी प्रयास करने की दिशा में हमने वहां पर अभी प्रेजीडेंट रूल लगाया है । और मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जल्द से जल्द दो-चार दिन के अंदर ही वहां एक नये गवर्नर, जो फुल-टाईम गवर्नर होंगे वहां के लिए, उनकी पद-स्थापना हो जाएगी । साथ ही साथ उनके आने के बाद जितनी जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरी की जा सके और जिसको भी बहुमत होगा, वह अपनी सरकार बनाने के लिए वहां से सक्षम होगा ।

माननीय सदस्यों की राय थी कि एडवाइजरी कौंसिल इस बीच में बनाई जाए और वहां के एडवाइजर्स के संबंध में जो कहा गया है, जब तक वह सरकार नहीं बनती है, वहां के जो एम०एल०एज० हैं, उन तमाम लोगों को भी कांफीडेंस में लेकर के सरकार के कार्यकलाप में उनकी भागेदारी हो यह भी प्रक्रिया हम कोशिश करेंगे कि वहां जल्दी शुरू कराई जाए ।

अगर हमें अपनी मंशा होती, जैसा कि यह कहा गया कि गवर्नर से अपने मन की लायक रिपोर्ट मंगवाई जाती है, यह चार्ज लगाया गया । जब कि गवर्नर की रिपोर्ट से अलग हट कर के वहां के बेस्ट के लिए जो हो सकता था, वह व्यवस्था करने की कोशिश की गई है, जिससे कि वहां पर चुने हुए प्रतिनिधियों की सरकार बने ।

इन चंद शब्दों के साथ मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि गोवा की जो अपनी कल्चरल हेरिटेज है, उसको बचाते हुए और आज वहां पर टूरिस्ट सीजन है, जिसमें अपने आप में गोवा एक आकर्षक स्थल है, उन तमाम बिंदुओं को देखते हुए, वहां पर कोई प्रशासनिक अक्षमता न रहे, इस पर भी मैं पूरा ध्यान देने की कोशिश करूंगा और जो वहां पर एडवाइजर है या गवर्नर जो जायेंगे, वह इसको प्राथमिकता के तौर पर देखेंगे ।

इन चंद शब्दों के साथ मैं फिर सदन से अनुरोध करता हूं कि इसका अनुमोदन करें ।

SHRI M. M. JACOB (Kerala): A reference was made to Mr. George Feraoan-des going there and trying to topple the Government there.

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): I raised it.

SHRI M. M. JACOB: Mr. Narayanan samy raised it. What about that?

SHRI V. NARAYANASAMY:] want a specific answer to my question from t{ie honourable Minister.

श्री सुबोध कांत सहाय : उपसभाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री नरायणसामी जी

[श्री सुबोध कांत सहाय]

ने यह सवाल उठाया था और यह सवाल उठाये गये थे कि उस वक्त के जो तत्कालीन मंत्री थे, उन्होंने जाकर के सरकार को वहां पर तोड़ा ।

मैं उस हद तक, कहां तक उसमें पूरी सत्यता है, लेकिन गोवा की सरकार तीन-चार बार वहां पर बदली जा चुकी है और जिस राजनीतिक दलों को थोड़ा भी अपना जोर और शक्ति होती है, वहां अपनी आजमाईश करने की कोशिश करते हैं ।

आज अभी हमारे पास 30 दिसम्बर की रिपोर्ट्स में कहा गया है--जो गवर्नर ने रिपोर्ट्स भेजी है, उसमें भी कहा गया है कि वहां एक ग्रुप जो पहले से और था, उन्होंने अपना नाता-रिश्ता पार्टी से तोड़ लिया है और रवी नायक ग्रुप जो कांग्रेस (आई) की लेजिस्लेटिव पार्टी के थे, तेरह एल०एम एज० के साथ वह इंडिपेंडेंट एस० एल० एज० को लेकर के अपना बहुमत सिद्ध करने की बात कर रहे हैं ।

महोदय, तीन मेंबर जो गोवंस पीपल्ज पार्टी के थे, वह लोग भी रवी नायक को सपोर्ट कर रहे हैं और इस तरीके से गाहे-बगाहे सरकार बदलने से इन छोटे राज्यों में कुछ राजनीतिक असर बनाने की कोशिश की जाती है । लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो परम्परा रही है, इन छोटे राज्यों का गठन इसलिए किया गया था कि वहां की जनता की भागेदारी हो । वह अपना पीपल्ज मेंडेट के आधार पर अपनी सरकार चलाये और ऐसे राज्यों में स्टेबिल्टी भी रहे । यह हरेक राजनीतिक दलों की सोच होनी चाहिए । अगर इन राज्यों में इनस्टेबिल्टी अपनी राजनीतिक शक्ति लगा कर करने की कोशिश की जाएगी, तो वहां पर जो राजनीतिक परंपरा है, तो डेमोक्रेटिव सेट-अप है, उस पर कहीं न कहीं एक प्रश्नसूचक चिन्ह खड़ा हो जाएगा ।

छोटे राज्यों में, जो यह घटना खास कर गोवा में हुई है, मैं समझता हूं कि नारायणसामी जी ने जो सवाल उठाया, उनमें किस हद तक सत्यता है, इसको मैं नहीं जानता, लेकिन वहां की सरकारें उस वक्त बदली हैं । यह एक हकीकत है कि सरकार उस वक्त बदली थी । मैं इतना कहना चाहता हूं और इन चीजों के बाद भी आज वहां....

SHRI V. NARAYANASAMY: I put a specific question. On the first day, Mr". George Fernandes goes tlisre and on the second day the Government is toppled... *{Interruptions)*

SHRI PARVATHANENT UPENDRA: Yes, in one day it is toppled.. - *(Interruptions)...*

SHRI V. NARAYANASAMY: You can take credit for that.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): You have raised it twice or thrice. The Minister has replied to it. That is all.

SHRI V. NARAYANASAMY: But money power has played a major role. Did he topple the Congress(I) Government in Goa? *(Interruptions)*

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): आपका जवाब खत्म हुआ।.. **(व्यवधान)**

श्रीमती सुषमा स्वराज : वह उनके आरोपों का कैसे जवाब दें उस सरकार में भी सुबोध कान्त जी गृह मंत्री थे और अब इस सरकार में भी सुबोध कान्त जी गृह मंत्री हैं । कैसे जवाब दें ? उनकी दविधा समझिए ।

(Interruptions)

SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV (Maharashtra): Mr. Vice-Chalrman, Sir, it is very clear. Mr George Fernandes definitely played a significant role in toppling the Congress (I) Government. It is a known *inct. (Interriiptions).*

SHRIMATI MARGAREr ALVA (Karnataka): He should know. He should tell us.

SHRI JOHN F. FERNANDES (Goa): Actually I asked a specific question from the Home Minister: what is the latest po-sition? According to my report, CDF had 23MLAs and the Opposition only 15.

श्री चतुरानन मिश्र मंत्री महोदय ने कहा कि कुछ एम.एल.ए. इधर से उधर हो जाते हैं और उधर के एम.एल.ए. इधर चले आते हैं । यह ऐसा हो रहा है । हमको तो ऐसा लगता है उपसभाध्यक्ष महोदय, कि बंदर को जितना टाइम लगता है एक डाली से दूसरी डाली पर जाने में उससे कम टाइम लगता है राजनीतिक दल के लोगों को, लेकिन जब एम.पी. लोग ऐसा कर सकते हैं तो एम.एल.ए. क्यों नहीं करेगा ? यह हमको बताइये।

श्रीमती मारग्रेट आल्वा : इसी के लिए तो आपने तीन हफ्ते का टाईम मांगा था, इसी काम के लिए वी.पी. सिंह ने 3 हफ्ते का टाईम मांगा था ।

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : उनके साथ यह भी रहते हैं इधर-उधर जाने में, इस डाली से उस डाली पर भागने वाले परिंदों के साथ यह भी रहते हैं बड़े आराम से ।

श्री चतुरानन मिश्र: हमारी ही पार्टी है जिसका शुरू से अभी तक न सिंबल बदला है... **(व्यवधान)** सुनिए, न सिंबल बदला है और न नाम बदला है ।... **(व्यवधान)** हम सी. पी. आई. की तरफ से बोल रहे हैं, आप इंदिरा कांग्रेस की तरफ से... **(व्यवधान)** The CPI has never changed its symbol.

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): मेरे आदेश के बिना कही गई एक भी बात रिकार्ड में नहीं आएगी । मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि अभी गोवा के बाद आसाम का करेंगे और हम लोगों को बहुत आवश्यक मूल्य वृद्धि पर हाउस में डिसकशन करना है, इसलिए उसमें सहयोग करें । माननीय मंत्री महोदय से मैं कहता हूं कि वह अब इसको समाप्त करें ।

श्री सुबोध कांत सहाय : उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे बुजुर्ग और बहुत ही श्रद्धेय हैं मिश्रा जी, उन्होंने एक सवाल उठा दिया है, जिस सवाल पर राजनीतिक जीवन की मैंने अपनी राजनीति शुरू की है, मैं मानता हूं इस देश में सांप्रदायिकता का सवाल जब बहस का मुद्दा बनेगा तो उस वक्त यह फैसला करना पड़ेगा कि देश में सरकार सांप्रदायिक सवालों पर चुनाव में जाएगी जनता के बीच या शांति व्यवस्था बना करके देश में स्थिरता कायम करने की बात कहेगी । मैं उस वक्त के तत्कालीक जो प्रधान मंत्री थे उनसे भी इस सवाल पर बहस किया था कि आप आज के सवाल पर जब यह सवाल बहस का मुद्दा बनाए हैं तो आप बताइये हम देश की तमाम सैक्युलर शक्तियां जो हैं उनको एक साथ ले करके सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा आज खतरा है . . . **(व्यवधान)**

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) सुबोध कान्त सहाय जी, एक मिनट आप बैठिए । ऐसा है कि हम गोवा के ऊपर अभी लेंगे, देखिए एक दूसरी बहस हम शुरू करने नही जा रहे है और मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । . . . **(व्यवधान)** देखिए, मैं उसकी अनुमति नहीं दे रहा हूं । इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करूंगा कि यह जो गोवा के बारे में है उसी के बारे में बात करके आप समाप्त करें, यह मैं आपसे कहूंगा ।

MISS SAROJ KHAPARDE (Maharashtra): Either you come this side and ask,

{Interruptions}

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, आप यहां नहीं वहां बैठे हैं, आपकी नजरें बराबर हो । . . . **(व्यवधान)**

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : आप इससे ऊपर हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) : देखिए, मैंने उनको भी मना किया है, आपको भी मना करता हूं । . . . **(व्यवधान)**

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : आप जवाब आने दीजिए, उन्होंने जवाब मांगा है।.... (**व्यवधान**) जवाब मिल रहा है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): He is already giving the reply.

श्री सुबोध कांत सहाय : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपकी भावना के साथ मैं गोवा पर ही हूं और चुनाव क्यों नहीं कराए जाए, इसी सवाल पर मैं कह रहा हूं कि जो हमारी स्थिति है, चाहे वह कानून और व्यवस्था की हो, चाहे सांप्रदायिकता की हो--यह लहर देश के हरेक कोने में फैली हुई है। इसीलिए यहां पर एक पीपुल्स गवर्नमेंट बनी और चुनाव के मैदान में तत्काल न जाएं, इसी सवाल को लेकर गोवा में सरकार बनायी है और इस देश में सरकार बनायी है जिसका कि मैं गृह मंत्री होकर आपके बीच में खड़ा हूं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि यह सदन इस प्रस्ताव का अनुमोदन करेगा।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRISHANKAR DAYAL SINGH): I shall now put the Resolution moved by Shri Subodh Kant Sahay to move:

The question is:

"That this House approves the Proclamation issued by the President on the 14th December, 1990, under article 356 of the Constitution, in relation to the State of Goa. "

Thr motion was adopted.

1 RESOLUTION SEEKING APPROVAL OF PRESIDENTS PROCLAMATION UNDER ARTICLE 356 IN RELATION TO ASSAM; &....

2| MOTION RECOMMENDING REVOCATION OF THE PROCLAMATION

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा सूचना और प्रसार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोधकांत सहाय): उप सभाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करता हूं :—

"यह सभा संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन असम राज्य के संबंध में राष्ट्रपति द्वारा 27 नवम्बर, 1990 को जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है।"

महाशय, असम के राज्यपाल की रिपोर्ट और उद्घोषणा की प्रतियां सदन के पटल पर रखी गयी हैं। असम के राज्यपाल ने भारत के राष्ट्रपति को 26 नवम्बर, 1990 की अपनी रिपोर्ट में यह बताया कि यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आफ आसाम (उल्फा) ने भारत के संविधान से आसाम को मुक्त कराने के लिए सशस्त्र संघर्ष शुरू कर दिया है तथा वे एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राज्य की स्थापना के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए उसने चुने हुए व्यक्तियों को गोली मारकर हत्या कर के तथा समाज के समृद्ध वर्ग से धन ऐंठने के लिए आतंक का उपयोग कर के लोगों के बीच डर की भावना पैदा करने की दोहरी नीति अपनायी है। राज्यपाल ने बताया है कि उल्फा द्वारा 13 निर्दोष व्यक्तियों की गोली मारकर हत्या की गयी। बदला लेने के अभियान को जारी रखते हुए उल्फा कार्यकर्ताओं ने बाकायदा ऐसे पुलिस अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं की हत्या की जो उनके उद्देश्य की प्राप्ति की राह में आते थे। पिछले तीन वर्षों के दौरान 58 राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हत्या की गई तथा 19 अधिकारियों का वध किया गया है। राज्यपाल ने यह भी उल्लेख